Statement

(Rs. Crores/Thousand Hectares)

S. No.	State/UTs	Irrigation Potential Created at the end of		Unutilised at the end of		Total Plan Expenditure 1951-92
		Seventh Plan (1985-90)	Annual Plan (1991-92)	Seventh Plan (1985-90)	Annual Plan (1991-92)	
1.	Andhra Pradesh	2991	2999	155	152	3445.10
2.	Arunachal Pradesh	—	—	—	—	2.38
3.	Assam	144	176	47	65	287.55
4.	Bihar	2743	2766	484	471	3132.60
5.	Goa	13	13	8	1	111.77
6.	Gujarat	1199	1246	344	260	3472.07
7.	Haryana	2021	2035	230	244	1184.17
8.	Himachal Pradesh	8	8	2	4	26.54
9.	Jammu & Kashmir	158	158	41	22	206.11
10.	Karnataka	1308	1377	125	185	1875.70
11.	Kerala	402	416	47	49	908.22
12.	Madhya Pradesh	1815	1962	546	567	2885.56
13.	Maharashtra	1986	2030	1010	994	4419.41
14.	Manipur	59	59	13	9	196.71
15.	Meghalaya	—	—	—	—	1.37
16.	Mizoram	—	—	—	—	0.50
17.	Nagaland	—	—	—	—	0.25
18.	Orissa	1356	1409	102	83	1530.20
19.	Punjab	2344	2367	41	58	722.53
20.	Rajasthan	1913	1999	173	112	1667.41
21.	Sikkim	—	—	—	—	1.10
22.	Tamil Nadu	1539	1545	3	4	643.04
23.	Tripura	2	2	0	—	65.24
24.	Uttar Pradesh	6667	6806	962	1043	3666.17
25.	West Bengal	1244	1353	112	95	67.93
	Total (States)	29912	50726	4445	4418	30519.63
	Total (UTs)	8	15	8	8	117.29
	Total (All India)	29920	30741	4453	4426	30636.92

मध्य प्रदेश में आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए योजना

3426. **श्री नारायण प्रसाद गुप्ता:** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश में बिलासपुर के पिछड़े हुए आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए कोई योजना भेजी है;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कल्याण मंत्रालय ने योजना को प्रशासनिक मंजूरी दे दी है; और

(घ) यदि हां, तो वित्तीय मंजूरी कब तक दे दी जाएगी और राज्य सरकार को कितनी धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): (क) और (ख) जी, हां। मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश के बिलासपुर प्रभाग की समेकित आदिवासी विकास परियोजना के लिए परियोजना रूपरेखा तैयार की है जिसे अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, रोम द्वारा वित्त पोषित किया जाना है। परियोजना 45 आदिवासी विकास प्रखंडों के लिए अभीष्ट है जहां अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 59% है। परियोजना की कुल अनुमानित लागत 450 करोड़ रुपये है।

(ग) और (घ) यह परियोजना प्रस्ताव अन्तर्राष्ट्रीय

कृषि विकास कोष, रोम से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए है। इस मंत्रालय ने इस मामले में आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय के पास सिफारिश की है, कि वह वित्तीय सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, रोम के साथ मामला उठाए। आर्थिक कार्य विभाग ने सूचित किया है कि मामले को अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, रोम के साथ उठाया गया है। इस स्तर पर यह कहना सम्भव नहीं है कि वित्तीय अनुमोदन कब तक दिया जा सकेगा तथा राज्य सरकार को कितनी धनराशि प्रदान की जाएगी।

मध्य प्रदेश में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र

3427. **श्री नारायण प्रसाद गुप्ता:** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तीन व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, जिनकी स्वीकृति केन्द्रीय सरकार द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के लिये दी गई है, राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की काफी जनसंख्या को देखते हुए पर्याप्त है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार आवश्यकतानुसार अधिक व्यावसायिक केन्द्र खोलने पर विचार कर रही है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): (क) जी, नहीं।

(ख) सरकार पिछले वर्ष अनुदान की निर्मुक्ति के मामले में मध्य प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्ताव पर विचार करेगी बशर्ते कि उपयोग प्रमाण पत्र तथा प्रगति रिपोर्ट आदि जैसी विहित शर्तें पूरी की गई हों।

Plight of Senior Citizens

3428. SHRI KRISHAN LAL SHAMRA: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that plight of senior citizens of the country is full of misery and despair;

(b) whether Government have taken any census of such persons; and

(c) whether Government have drawn a plan for their welfare by enlarging the scope of social security?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI): (a) It cannnot be generalised that the plight of all Senior Citizens of the country is full of misery and despair, it is not unlikely that many of them may not be in a comfortable position both economically and emotionally. The family ties in India are genrally still intact and the welfare of the elderly is taken care of by the family. In the organised sector, the retired persons get pension and other terminal benefits. The State Governments are providing Old Age Pension to the aged people.

(b) The age data of 1991 census is under process. However, as per 1981 census, the number of aged persons of 60 years of age and above was 4.32 crores approximately.

(c) The Government has drawn a scheme of assistance to voluntary organisations for programmes relating to the aged for providing physical, social, emotional, psychological and economic support to the aged (60 years and above) with a view to help them to continue to be usefully active members of the community. Under this scheme, grants-in- aid were released to the voluntary organisations for running 126 Old Age Homes, 182 Day Care Centres and 11 Mobile Medicare Units.

शुष्क शौचालयों का संप्रवाह व्यवस्था में परिवर्तन

3429. **श्रीमती आनन्दीबेन जेठाभाई पटेल:** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में संप्रवाह शौचालय व्यवस्था में परिवर्तित किये गये शुष्क शौचालयों की संख्या कितनी है तथा इस संबंध में राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) शुष्क शौचालयों के परिवर्तन के बाद सफाई करने के काम से मुक्त हुए सफाई कामगारों की संख्या कितनी है तथा उन्हें विभिन्न व्यवसायों में पुनर्वासित करने के लिए सफाई कामगारों और उनके परिवारों को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है तथा तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): (क) और (ख) अल्प लागत स्वच्छता योजना के अंतर्गत शुष्क शौचालयों को जलवाहित (संप्रवाह) शौचालयों में परिवर्तन की राज्य वार संख्या और इसके द्वारा मुक्त किए गए सफाई कर्मचारियों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है (नीचे देखिए) तथा सफाई कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों की मुक्ति और पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना के अधीन सफाई कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों को विभिन्न